RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-11
November -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

राजस्थान में 12वीं से 14वीं विधानसभा चुनावों में जातिगत राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन

अशोक कुमार यादव

पीएच.डी. छात्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 15 November 2018

Keywords
राजस्थान, राजनीति, जाति, धर्म तथा भाषा

ABSTRACT

राजस्थान की राजनीति में जाति, धर्म तथा भाषा तत्वों का महत्व राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में अधिक होता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् 30 मार्च 1949 को राजस्थान भारत के एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय से लेकर आज तक राजस्थान की धरती में कई उतार–चढ़ाव देखने को मिले है। राजस्थान की राजनीति में भी कई दिग्गज आए और गए लेकिन राजस्थान की जनता हर बार 5 वर्षों में सरकार से हिसाब लेना बखूबी जानती है। वहीं समय के साथ जैसे–जैसे राजस्थान की आबादी बढ़ी है, वैसे–वैसे राजस्थान में जातीय समीकरण नेताओं के फायदे और नुकसान दोनों की वजह रहा है। राजस्थान में हमेशा से ही विधानसभा चुनावों में राजपूत–जाट जातियों के द्वारा ही राज्य की दिशा तय की जाती रही है। परन्तु पिछले कुछ चुनावों से ये समीकरण बदलते जा रहे है। जहां राजपूत मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां कोई गैर–जाति का सदस्य जीतकर विधानसभा में अपनी पहुंच बना रहा है। इससे प्रतीत होता है कि अब राज्य में जातियों के प्रभाव की अपेक्षा व्यक्ति का प्रभाव अधिक मायने रखता है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में जातिगत राजनीति

कांग्रेस ने पिछली विधानसभा (2003) में हार का कारण यह माना था कि चूंकि जाट और ब्राह्मण मतदाता उससे नाराज हो गये हैं। इसलिए उन्हें राजी करने के लिए इन दोनों जातियों को नेतृत्व संभलवाया जाये। यही मांग प्रदेश स्तर पर भी नेताओं ने की थी जिसे ध्यान में रखकर केन्द्र ने उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को मनोनीत किया था। सामंतवाद के विरुद्ध प्रारम्भ हुआ स्वतंत्रता का आंदोलन जातिवाद पर आकर कैसे टिका? यह स्वतः प्रमाणित है। अब वोट का आधार योग्यता, काम, सेवा तथा सिद्धान्त न रहकर केवल मात्र जातिवाद हो गया है।[1]

राजस्थान में वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के बाहुल्य वाली सीटों पर जनता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही मीणा जाति के प्रत्याशी होने पर बस्सी में धानका जाति की अंजु खंगवाल और राजगढ़–लक्ष्मणगढ़ से सूरजभान धानका अन्य जातियों के समर्थन से जीते थे। राजनीतिक दल भले ही जातिगत प्रत्याशी खड़े करे लेकिन आम मतदाता को दोनों दलों के साथ चाहे योग्यता के नजरिये से हो अथवा अन्य किसी दृष्टि से, जहां भी कोई अन्य विकल्प मिल जाता है तो जनता उसेक चुन लेती है। जाति के जहर की असली काट भी यही है।

राज्य विधानसभा के पिछले तीन चुनावों में टिकट वितरण से लेकर सरकार गठन तक एससी–एसटी और जाटों का ही बोलबाला रहा है। प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा ने 95 से ज्यादा सीटों पर इन्हीं वर्गों के प्रत्याशी उतारे। बाकी आधी सीटों का राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, गुर्जर और अन्य जातियों में बंटवारा होता है। एससी–एसटी और जाटों के बाद दोनों पार्टियों में ब्राह्मण उम्मीदवारों का बराबर का दबदबा रहा। बची हुई असरदार जातियों में कांग्रेस ने मुस्लिम तो भाजपा ने वैश्य व राजपूत समाज के उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो दी। वर्ष 2008 के चुनाव में कांग्रेस व भाजपा ने एससी–एसटी के क्रमशः 35 और 28 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया। दोनों पार्टियों ने इन वर्गों के बाद जाट जाति के सर्वाधिक प्रत्याशी उतारे। भाजपा ने 32 व कांग्रेस ने 33 जाट प्रत्याशियों को टिकट दिए। टिकट वितरण में चौथे नंबर पर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को तवज्जो दी और 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं भाजपा ने राजपूत समाज को 30 सीटों से चुनाव लड़ाया।[2]

ब्राह्मण समाज पर दोनों ही दलों ने लगभग बराबर फोकस किया। भाजपा ने 18 और कांग्रेस ने 20 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे। भाजपा ने राजपूतों को ज्यादा टिकट दिए, जबकि कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले राजपूत समाज के 10 प्रत्याशी कम उतारे। कांग्रेस ने 20 सीटों पर राजपूत उम्मीदवारों को टिकट दिए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान एकजुट हुए गुर्जर समाज के वोटों को देखते हुए भाजपा ने पिछले तीन चुनाव में क्रमशः 8, 11 व 7 प्रत्याशी तो कांग्रेस ने क्रमशः 10, 9 और 9 प्रत्याशी मैदान में उतारे।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका 1: वर्ष 2003 एवं 2008 के विधानसभा चुनावों में विधायकों का तुलनात्मक जातिवार विवरण[3]

जाति–वर्ग	2003		2008	
	कांग्रेस	भाजपा	कांग्रेस	भाजपा
एससी	5	26	18	14
एसटी	6	20	18	3
जाट	15	12	16	8
राजपूत	5	18	8	16
वैश्य	5	13	4	12
ब्राह्मण	8	9	6	7
मुस्लिम	4	1	10	2
गुर्जर	2	6	3	3
माली	1	1	2	1
कलबी	0	4	2	1
यादव	0	2	1	2
कुमावत	0	3	1	1
पंजाबी	1	3	0	2
सिख	–	–	1	0
सिंधी	0	1	0	2
रेबारी	–	–	1	1
कलाल	1	1	2	0
रावत	0	1	0	2
सिरवी	–	–	0	1
धाकड़	0	2	1	0
विश्नोई	0	1	1	0
डांगी	0	1	1	0
माथुर	1	0	–	–
कुल	**54**	**125**	**96**	**78**

तालिका 1 में उपरोक्त विवरण के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2003 एवं 2008 के विधानसभा चुनावों में विधायकों को जाति के आधार पर बांटा गया है। जिसमें ज्यादातर जातियों के सर्वाधिक उम्मीदवार भाजपा दल के है।

तालिका 2: वर्ष 2003 एवं 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एवं भाजपा द्वारा एक खास जाति के प्रत्याशियों को आमने–सामने उतारा[4]

जाति	विधानसभा सीट	
	2003	2008
ब्राह्मण	रतनगढ़, सीकर, सांगानेर, बीकानेर, हवामहल, बांसवाड़ा, बूंदी	रतनगढ़, बीकानेर पूर्व, सीकर, सांगानेर, हवामहल
राजपूत	बनीपार्क, राजाखेड़ा, शेरगढ़, ओसियां, वल्लभनगर, जैसलमेर, चितौड़गढ़	विद्याधरनगर, परबतसर, लोहावट, शेरगढ़, वल्लभनगर, जैसलमेर, माण्डलगढ़, कुंभलगढ़
जाट	सादुलपुर, किशनगढ़, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, संगरिया, झुंझुनूं, धोद, दांतारामगढ़, खंडेला, आमेर, करणपुर, भोपालगढ़, बिलाड़ा, कुम्हेर, डीग, नदबई, मुंडावर, नागौर, मंडावा	सादुलपुर, मंडावा, सुरजगढ़, करणपुर, सूरतगढ, किशनगढ़, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा, खंडेला, लक्ष्मणगढ, विराटनगर, डीग–कुम्हेर, नदबई, खींवसर, डेगाणा, ओसियां, गुढ़ामलानी
वैश्य	कोटा, सिरोही	राजाखेड़ा
मेघवाल/मोची/जाटव/बैरवा	सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़, अजमेर दक्षिण, केकड़ी, रायसिंहनगर, फागी, बसेड़ी, अलवर ग्रामीण, रूपावास, वैर, राजसमंद, शाहपुरा, कठूमर, खंडार, हिंडौन, निवाई, पाटन, पीपल्दा, डग, रेवदर, जालौर, सिवाणा, सूरसागर, जायल, परबतसर,	सुजानगढ़, पिलानी, रायसिंहनगर, अनूपगढ, पीलीबंगा, अजमेर दक्षिण, धोद, कठूमर, वैर, बसेड़ी, सिकराय, जायल, मेड़ता, सोजत, जालोर, शाहपुरा, कपासन

RRIJM 2015, All Rights Reserved

जाति	विधानसभा सीट	
	2003	2008
	सूरजगढ़	
गुर्जर	नसीराबाद, खेतड़ी, बयाना	नसीराबाद, खेतड़ी, नगर
रावत	भीम	ब्यावर, भीम
सिंधी	अजमेर उत्तर	–
यादव	बहरोड़	बहरोड़
मीणा	लालसोट, राजगढ, प्रतापगढ, घाटोल, कुशलगढ, बागीदौरा, सागवाडा, चौरासी, डूंगरपुर, आसपुर, लसाडिया, उदयपुर ग्रामीण, सलूंबर, सराडा, खेरवाडा, फलासिया, गोगूंदा, किशनगंज, सपोटरा, बामनवास, टोडाभीम, दानपुर, पिंडवारा, आबू	राजगढ–लक्ष्मणगढ, टोडाभीम, गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, सलूम्बर, धरियावाद, डूंगरपुर, आसपुर, सागवाड़ा, चौरासी, घाटोल, बांसवाड़ा, गढ़ी, बागीदौरा, प्रतापगढ़
मुस्लिम	–	कामां

तालिका 2 में उपरोक्त विवरण के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2003 एवं 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एवं भाजपा द्वारा एक खास जाति के उम्मीदवारों को आमने–सामने उतारा गया है। जिसमें ज्यादातर उम्मीदवार मीणा, जाट एवं राजपूत जातियों के दर्शाये गए है।

राजनीतिक दल और राजनेता भले ही उम्मीदवारों के चयन में जाति–समुदाय को तरजीह नहीं देने की बाते करते हों लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों (भाजपा एवं कांग्रेस) के विधानसभा चुनाव के घोषित उम्मीदवारों पर अगर नजर डाले तो ऐसा लगता है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में जाति के आधार पर उम्मीवार चुने गये है। चुनाव चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के या फिर स्थानीय स्तर के, जाति के आधार पर उम्मीदवार तय करना तो जैसे राजनीतिक दलों के आचरण में ही शुमार होने लगा है। तात्कालिक फायदे के लिए भले ही राजनीतिक दल जातिवाद के जहर को आम जनमानस में घोलने में लगे हों पर इनके दूरगामी परिणाम सदैव नुकसानदायक होते रहे हैं। जाति के आधार पर टिकट लेने वाला प्रत्याशी भी वोट मांगने के लिए बाद में खुद को छत्तीस कौमों के समर्थन की बात कहता है।[5]

राजस्थान में 14वीं विधानसभा चुनाव के लिए घोषित प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा एवं कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची देखें तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये चुनाव प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के हो रहे हैं। एक ही जाति के प्रत्याशी जाति से भी नीचे उतरकर गौत्र और कबीलों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में संबंधित क्षेत्र में निवास कर रहे अन्य मतदाताओं के लिए चुनाव तमाशा बन जाता है और उसके कदम मतदान केन्द्र की तरफ उठते ही नहीं। कारण साफ है जातिवाद की विषबेल इतनी बढती जा रही है कि उस क्षेत्र में दूसरी जातियों के मतदाता खुद को असुरक्षित महसूस करते है। राजस्थान में दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि ऐसे क्षेत्रों है जो जातिवाद से सर्वाधिक प्रभावित है।[6]

राजस्थान में मुस्लिम आबादी करीब 9 प्रतिशत है। नागौर, सीकर, चुरू, जयपुर, भरतपुर और टौंक जिले में इनकी 10 प्रतिशत है। विधानसभा चुनाव 2013 में कांग्रेस पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक निर्वाचित नहीं हुआ। 200 विधानसभा सीट में भाजपा ने केवल 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया। इसमें से दो निर्वाचित हुए। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने किसी भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी के भी मात्र एक उम्मीदवार मुस्लिम है। क्रिकेटर हैदराबाद निवासी अजहररूद्दीन टोंक सवाईमाधोपुर क्षेत्र से उम्मीदवार है। मुस्लिम आबादी एवं कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट देने के हिसाब से दो मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए था। नागौर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के दो मुस्लिम विधायक हबीकर्रहमान अशरफी और युनुस खान निर्वाचित हुए। युनूस खान अभी भाजपा सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सी.आर. चौधरी के पक्ष में मतदाताओं में रूझान पैदा नहीं कर पाए। मुस्लिम मतदाता नरेन्द्र मोदी के 2002 में हुए गुजरात दंगों में तथाकथित भूमिका का विरोध कर रहे हैं।[7] वैसे मुस्लिम मतदाता किसी गैर मुस्लिम भाजपा उम्मीदवार को वोट नहीं देता है। मुस्लिम मतदाता भाजपा उम्मीदवार को हराने के लिए किसी सशक्त गैर भाजपा उम्मीदवार को समूह के रूप में राजस्थान में मतदान करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी पहली पसन्द है।

2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड 163 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी 102 से सिमटकर महज 21 सीटें ही जीत पाई। राज्य में कांग्रेस की यह सबसे बुरी हार थी। गहलोत सरकार

RRIJM 2015, All Rights Reserved

के मंत्रिमण्डल के अधिकांश सदस्य चुनाव हार गए थे। किरोड़ीलाल की नई पार्टी राजपा को महज 4 सीटें मिली थी। जमींदारा 2 सीट, बसपा 3 और निर्दलीयों ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस तरह 2013 के विधानसभा चुनावों में जनता ने एकपक्षीय बहुमत भाजपा के हाथ में सौंप दिया।

कांग्रेस की गहलोत सरकार की ओर से किए गए तमाम विकास के दावों को नकारते हुए जनता ने एकपक्षीय बहुमत देकर प्रदेश में 5 वर्षों बाद भाजपा को सत्ता सौप दी। साथ ही जनता ने अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी कि वे हर 5 साल में नई सरकार को मौका देना चाहते हैं। वर्ष 1998 में भाजपा को हटाकर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के हाथों में जनादेश दे दिया था। जिसमें प्रदेशवासियों ने भाजपा और कांग्रेस की सरकार को एक के बाद एक करके मौका दिया था। प्रदेश में 200 सीटों के परिणामों में भाजपा ने 163 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटें मिलीं। 16 सीटें अन्य दलों के खाते में गई, इनमें किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी राजपा को 4, बसपा को 3 और 9 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी।[8]

सारांश

राजस्थान में विभिन्न जातीय संगठन हैं जो शक्ति, सत्ता एवं सांस्कृतिक संरचना पर आधारित है पिछले कुछ दशकों से यह चलन बहुत तेजी से चल पड़ा कि अगर जातियां संगठित होती हैं तो वे अपने हितों को उचित प्रकार से पूरा कर सकती है, चाहे वह सरकार पर दबाव बनाकर अथवा अन्य किसी माध्यम से। यह भी माना जाता है कि ये संगठन समाज का परस्पर सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का भी अब तो एक सर्वोत्तम माध्यम है। दलीय व्यवस्था में जाति की भूमिका के आधार पर राजनीतिक दलों में लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों के चयन और उनके निर्वाचन में भी जातिवाद का प्रभाव दिखाई दिया है। राजस्थान में जाति के आधार पर दलीय व्यवस्था की दृष्टि से प्रथम विधानसभा चुनाव से लेकर वर्तमान तक के विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि समस्त पार्टियों ने अब तक विभिन्न जातियों को आधार बनाकर अपनी सत्ता की धाक जमाई है।

संदर्भ सूची

1. भण्डारी, विजय, ''राजस्थान में राजनीति सामन्तवाद से जातिवाद के भंवर में'', वाणी प्रकाशन, 2007, पृ. 98.
2. मिश्रा, रत्नेश कुमार, ''भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल'', रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011, पृ. 167
3. राजस्थान पत्रिका, 5.02.2009, पृ. 2
4. राजस्थान पत्रिका, 5.02.2009, पृ. 3
5. बिस्वाल, तपन, ''भारतीय शासन, संवैधानिक लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया'', ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रकाशन, 2017, पृ. 129
6. राजस्थान पत्रिका, 12.11.2013, पृ. 6
7. www.jagran.com/rajasthan/jaipur
8. दैनिक भास्कर, मार्च 2018, पृ. 8

RRIJM 2015, All Rights Reserved